

भारतीय विदेश नीति में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं में बदलाव : सार्क से बिस्मटेक तक

Sonu Kumar, Dr. Divya Nath

Professor

Department of Political Science, Km Mayawati Government Girls P.G College Badalpur
Gautam Buddha Nagar U.P India

Abstract (सारांश)

भारतीय विदेश नीति में पड़ोस और क्षेत्रीय सहयोग की प्राथमिकताएँ लंबे समय तक 1985 में स्थापित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) से जुड़ी रहीं, किंतु 2014 के बाद इनमें स्पष्ट पुनर्संयोजन दिखाई देता है। यह शोध-पत्र द्वितीयक आँकड़ों और प्रकाशित स्रोतों के आधार पर विश्लेषण करता है कि भारत का क्षेत्रीय झुकाव सार्क से बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिस्मटेक) की ओर कैसे और क्यों बढ़ा। अध्ययन में शिखर सम्मेलनों के घटनाक्रम, संस्थागत ढाँचे, अंतर-क्षेत्रीय व्यापार के अनुपात तथा संपर्क परियोजनाओं की तुलना की गई है। निष्कर्ष बताते हैं कि नवंबर 2014 में काठमांडू में हुए 18वें शिखर सम्मेलन के बाद सार्क का कोई शिखर सम्मेलन नहीं हो सका और 2016 में प्रस्तावित इस्लामाबाद सम्मेलन स्थगित हो गया; दूसरी ओर बिस्मटेक को 2022 में चार्टर, 2024 में उसका प्रभावी होना तथा 2025 में बैंकॉक विज़न 2030 और समुद्री परिवहन सहयोग समझौता प्राप्त हुए। फिर भी बिस्मटेक में अंतर-क्षेत्रीय व्यापार 2023 में लगभग 6.7 प्रतिशत है और मुक्त व्यापार समझौता अब तक अंतिम रूप नहीं ले सका है। शोध-पत्र का निष्कर्ष है कि यह परिवर्तन सार्क के परित्याग की अपेक्षा प्राथमिकताओं के पुनर्क्रम का मामला है, जिसमें सुरक्षा, संपर्क तथा 'पड़ोसी प्रथम' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों का समन्वय निर्णायक रहा है।

Keywords (प्रमुख शब्द): भारतीय विदेश नीति, सार्क, बिस्मटेक, पड़ोसी प्रथम, एक्ट ईस्ट, क्षेत्रीय सहयोग, बंगाल की खाड़ी।

I. INTRODUCTION (प्रस्तावना)

किसी भी देश की विदेश नीति में निकटवर्ती क्षेत्र का स्थान केवल भौगोलिक निकटता से तय नहीं होता; वह सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, संपर्क और राजनीतिक विश्वास के समेकित समीकरण से बनता है। भारत के संदर्भ में 1947 के बाद से विदेश नीति का क्रमिक विकास अनेक चरणों से गुज़रा है [1], और इन चरणों में दक्षिण एशिया के साथ संबंधों का स्वरूप बार-बार पुनर्परिभाषित हुआ है। प्रस्तुत शोध-पत्र इसी निरंतर पुनर्परिभाषा के एक विशेष पहलू, अर्थात् क्षेत्रीय सहयोग के संस्थागत मंच के चयन, पर केंद्रित है।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में आयोजित प्रथम शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के राष्ट्राध्यक्षों द्वारा चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई [2]। बाद में अफगानिस्तान के जुड़ने से सदस्य संख्या आठ हो गई। संगठन के 18 शिखर सम्मेलन 1985 से 2014 के बीच हुए, जिनमें अंतिम काठमांडू में 26-27 नवंबर 2014 को संपन्न हुआ। इसके बाद इस्लामाबाद में 2016 के लिए प्रस्तावित 19वाँ शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हो सका [3]।

इसके समानांतर, 6 जून 1997 की बैंकॉक घोषणा से अस्तित्व में आया बिस्मटेक, जिसके सात सदस्य देश बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड हैं, धीरे-धीरे दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सेतु के रूप में उभरा [4]। विगत एक दशक में भारत की क्षेत्रीय कूटनीति में बिस्मटेक की चर्चा और सक्रियता बढ़ी है, जबकि सार्क का शिखर-स्तरीय तंत्र ठप पड़ा है। अप्रैल 2025 में बैंकॉक में हुए छठे शिखर सम्मेलन ने इस प्रवृत्ति को नई दृश्यता दी [5]।

यह अध्ययन तीन प्रश्नों से संबद्ध है: (क) क्या भारत की क्षेत्रीय प्राथमिकताओं में सार्क से बिस्मटेक की ओर स्पष्ट स्थानांतरण दिखाई देता है; (ख) इस स्थानांतरण के प्रमुख कारक क्या हैं; और (ग) क्या बिस्मटेक सार्क का पूर्ण विकल्प है, या दोनों मंच अलग-अलग भूमिकाओं में बने हुए हैं। शोध-पत्र का क्रम इस प्रकार है: साहित्य-समीक्षा के बाद शोध-प्रविधि, फिर परिणाम एवं विवेचन, और अंत में निष्कर्ष।

II. LITERATURE REVIEW (साहित्य समीक्षा)

इस खंड में विषय से संबंधित उपलब्ध साहित्य की समीक्षा तीन भागों में की गई है। पहले भाग में भारतीय विदेश नीति पर हिंदी की पुस्तकों और हिंदी समसामयिक विश्लेषणों को देखा गया है, दूसरे भाग में सार्क और बिस्मटेक पर अंग्रेज़ी के शोध एवं विश्लेषण को, और तीसरे भाग में उस रिक्ति को चिह्नित किया गया है जिसे यह अध्ययन भरना चाहता है।

2.1 हिंदी साहित्य

भारतीय विदेश नीति पर हिंदी में उपलब्ध पुस्तकें इस विषय की ऐतिहासिक और वैचारिक पृष्ठभूमि प्रदान करती हैं। सुमित गांगुली की कृति 1947 से हाल तक भारत की विदेश नीति के क्रमगत विकास का लेखा-जोखा प्रस्तुत करती है [1]; राजीव सिकरी की पुस्तक विदेश नीति की चुनौतियों और रणनीति पर केंद्रित है [6]; और साधना पांडेय की पुस्तक स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए विदेश नीति के अतीत से वर्तमान तक के पक्षों का सामान्य परिचय देती है [7]। ये ग्रंथ विदेश नीति की समग्र रूपरेखा देते हैं; प्रस्तुत अध्ययन इसी रूपरेखा के भीतर क्षेत्रीय मंचों के बीच प्राथमिकता-परिवर्तन का प्रश्न उठाता है।

हिंदी में समसामयिक विश्लेषण प्रस्तुत करने वाली सामग्री में यह रेखांकित किया गया है कि भारत अब सार्क की तुलना में बिस्मटेक को अधिक महत्व दे रहा है और सार्क में पाकिस्तान की उपस्थिति से बार-बार गतिरोध उत्पन्न हुआ है [8]। मार्च 2020 की सार्क वीडियो-बैठक पर हिंदी की रिपोर्ट यह दर्शाती है कि संकट की स्थिति में भारत ने सार्क के मंच का भी उपयोग किया और कोरोना से मिलकर लड़ने पर बल दिया [9]।

2.2 सार्क और बिस्मटेक पर अंग्रेज़ी साहित्य

अंग्रेज़ी में उपलब्ध शोध एवं विश्लेषण सार्क की विफलता और बिस्मटेक की संभावनाओं को अलग-अलग कोणों से देखते हैं। ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन का विश्लेषण सार्क के गतिरोध के बीच सासेक (SASEC) और बीबीआईएन (BBIN) जैसी उप-क्षेत्रीय पहलों को अपेक्षाकृत सफल बताता है [10]। काठमांडू पोस्ट का संपादकीय साप्ताहिक की कमज़ोरियों, क्षेत्र में भारत के असमान आकार (जनसंख्या का लगभग 75, भूभाग का 62 और जीडीपी का 83 प्रतिशत) तथा चीन की बढ़ती उपस्थिति को सार्क की कमज़ोर प्रगति की व्याख्या में रखता है [11]। साउथ एशियन वॉयसेज़ का विश्लेषण अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को दक्षिण एशिया के कुल व्यापार का लगभग 5 प्रतिशत बताते हुए आसियान (25 प्रतिशत) और पूर्वी एशिया (35 प्रतिशत) से उसकी तुलना करता है [12]। विश्व बैंक की 2018 की रिपोर्ट भी दक्षिण एशिया के अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को क्षेत्र के कुल व्यापार का केवल 5 प्रतिशत बताती है [13]।

बिस्मटेक पर हाल के विश्लेषण संभावनाओं के साथ संरचनात्मक सीमाओं को भी रेखांकित करते हैं। सिंगापुर के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के दक्षिण एशिया अध्ययन संस्थान (आईएसएस) की ब्रीफ़ बैंकॉक शिखर सम्मेलन की उपलब्धियों के साथ यह भी दर्ज करती है कि 2023 में बिस्मटेक का अंतर-क्षेत्रीय व्यापार केवल 6.7 प्रतिशत रहा [14]। ईस्ट एशिया फ़ोरम का विश्लेषण बताता है कि बिस्मटेक ठोस आर्थिक एकीकरण स्थापित नहीं कर पाया है और लंबे समय से लंबित संपर्क परियोजनाओं के पूरा होने में तत्परता का अभाव दिखा है [15]।

2.3 शोध-रिक्ति

समग्र रूप से, इस अध्ययन के लिए देखे गए स्रोतों में घटनाओं का वर्णन अधिक है, जबकि एक ही ढाँचे में सार्क और बिस्मटेक की कालक्रमिक तथा तुलनात्मक संस्थागत समीक्षा कम मिलती है; विशेषकर हिंदी में अक्टूबर 2026 तक के घटनाक्रम को समेटने वाला ऐसा विश्लेषण सीमित है। यह शोध-पत्र इसी रिक्ति को भरने का प्रयास करता है।

III. RESEARCH METHODOLOGY (शोध-प्रविधि)

यह खंड अध्ययन की कार्यपद्धति स्पष्ट करता है। इसमें क्रमशः शोध के उद्देश्य, शोध-प्रश्न, शोध-प्रारूप एवं अध्ययन अवधि, आँकड़ों के स्रोत तथा अध्ययन की सीमाएँ दी गई हैं, ताकि विश्लेषण की आधारभूमि और उसकी परिधि पाठक के सामने रहे।

3.1 शोध के उद्देश्य

इस अध्ययन के उद्देश्य हैं: (i) सार्क के उद्भव, उपलब्धियों और 2014-2016 के बाद आए गतिरोध का कालक्रमिक विवरण तैयार करना; (ii) बिस्स्टेक के संस्थागत विकास का आकलन करना; (iii) भारत की क्षेत्रीय प्राथमिकताओं में परिवर्तन के कारणों का विश्लेषण करना; और (iv) बिस्स्टेक की सीमाओं तथा सार्क की भावी भूमिका का मूल्यांकन करना।

3.2 शोध-प्रश्न

अध्ययन तीन शोध-प्रश्नों पर आधारित है। पहला, क्या भारत की क्षेत्रीय प्राथमिकताओं में सार्क से बिस्स्टेक की ओर स्पष्ट स्थानांतरण दिखाई देता है? दूसरा, इस स्थानांतरण के प्रमुख कारक क्या हैं? तीसरा, क्या बिस्स्टेक सार्क का पूर्ण विकल्प है, या दोनों मंच अलग-अलग भूमिकाओं में बने हुए हैं?

3.3 शोध-प्रारूप एवं अध्ययन अवधि

अध्ययन वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक एवं तुलनात्मक प्रकृति का है। इसमें गुणात्मक विश्लेषण को आधार बनाया गया है और उसके साथ सीमित मात्रात्मक संकेतकों, जैसे अंतर-क्षेत्रीय व्यापार का अनुपात, जनसंख्या, संयुक्त जीडीपी, सदस्य संख्या और शिखर सम्मेलनों की संख्या, का उपयोग किया गया है। अध्ययन अवधि 1985 से 16 अक्टूबर 2026 तक है। विश्लेषण पाँच आयामों पर किया गया है: सदस्यता एवं राजनीतिक संदर्भ, संस्थागत क्षमता, आर्थिक संकेतक, संपर्क एवं सुरक्षा सहयोग, तथा भारतीय नीति-संरक्षण।

3.4 आँकड़ों के स्रोत

अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। आधिकारिक दस्तावेजों में बिस्स्टेक सचिवालय की प्रेस विज्ञप्ति तथा लेख [5], [16], सार्क चार्टर [2], भारत के प्रधानमंत्री का वक्तव्य [17], विश्व बैंक की प्रेस विज्ञप्ति तथा आँकड़े [13], [18] और भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय की हिंदी विज्ञप्तियाँ [19] सम्मिलित हैं। अन्य स्रोतों में हिंदी की पुस्तकें, हिंदी समसामयिक विश्लेषण, शोध-संस्थानों के विश्लेषण तथा डॉन, काठमांडू पोस्ट, डेक्कन हेराल्ड, द प्रिंट और द ट्रिब्यून जैसे समाचार माध्यमों की रिपोर्टें हैं। हिंदी स्रोतों को यथासंभव वरीयता दी गई है, और आँकड़ों का मिलान संस्थागत स्रोतों से किया गया है।

3.5 अध्ययन की सीमाएँ

(i) अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर निर्भर है; कोई सर्वेक्षण या साक्षात्कार नहीं किया गया। (ii) सार्क और बिस्स्टेक के व्यापार-अनुपात अलग-अलग वर्षों और अनुमान-पद्धतियों पर आधारित हैं, इसलिए उनकी तुलना संकेतात्मक है। (iii) 2025-2026 के घटनाक्रम अभी विकासशील हैं और समाचार-स्रोतों पर आधारित हैं; वे आगे बदल सकते हैं। (iv) पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पक्ष मुख्यतः उपलब्ध सार्वजनिक वक्तव्यों के माध्यम से ही लिया गया है।

IV. RESULTS AND DISCUSSION (परिणाम एवं विवेचन)

इस खंड में द्वितीयक स्रोतों से एकत्र तथ्यों को छह भागों में प्रस्तुत और विवेचित किया गया है। पहले दो भाग सार्क और बिस्स्टेक के विकास का क्रमवार विवरण देते हैं; तीसरा भाग दोनों संगठनों की तुलना करता है; चौथा भाग भारत की प्राथमिकताओं में परिवर्तन के कारकों को चिह्नित करता है; पाँचवाँ भाग बिस्स्टेक की सीमाओं का आकलन करता है; और छठा भाग यह विवेचन करता है कि बिस्स्टेक सार्क का प्रतिस्थापन है या पूरक।

4.1 सार्क: उपलब्धियाँ और गतिरोध

सार्क ने अपने आरंभिक दशकों में संस्थागत संरचना खड़ी की। मुक्त व्यापार के लिए साफ्टा (जनवरी 2004 में इस्लामाबाद सम्मेलन में हस्ताक्षरित, 1 जनवरी 2006 से लागू) इसका प्रमुख आर्थिक साधन रहा [20]। खाद्य सुरक्षा के लिए सार्क खाद्य बैंक और बीज बैंक भी इसी ढाँचे की उपज हैं। मई 2017 में भारत ने दक्षिण एशिया उपग्रह (जीसैट-9) को पाकिस्तान के अतिरिक्त सार्क पड़ोसियों के लिए उपहार स्वरूप प्रक्षेपित किया [21]।

इन उपलब्धियों के बावजूद आर्थिक परिणाम सीमित रहे। साफ्टा के बाद भी अंतर-सार्क व्यापार क्षेत्र के कुल व्यापार का लगभग 5 प्रतिशत ही रहा [13]; विश्व बैंक की 2016 की रिपोर्ट के हवाले से भी यह अनुपात पाँच प्रतिशत से कम बताया गया और दक्षिण एशिया को विश्व का सबसे कम एकीकृत क्षेत्र कहा गया [22]।

राजनीतिक मोर्चे पर निर्णायक मोड़ 2014-2016 के बीच आया। नवंबर 2014 के काठमांडू शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान की आपत्ति के कारण संपर्क संबंधी समझौतों पर सहमति नहीं बन सकी [23]। इसके बाद 18 सितंबर 2016 को उरी में हुए आतंकी हमले के पश्चात भारत ने इस्लामाबाद में नवंबर 2016 के लिए नियत 19वें शिखर सम्मेलन में भाग न लेने का निर्णय लिया [3]; बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने भी अनुपस्थिति की घोषणा की, और पाकिस्तान ने सम्मेलन के स्थगन की औपचारिक घोषणा की [3]। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने भारत पर सार्क के चार्टर की भावना को आहत करने का आरोप लगाया [3]। दिसंबर 2025 में सार्क चार्टर दिवस की 40वीं वर्षगाँठ पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के भाग न लेने से प्रक्रिया रुक गई और पिछले 11 वर्षों से सार्क ठहरा हुआ है [24]।

सार्क की व्यवहार्य भूमिका का एक उल्लेखनीय उदाहरण 15 मार्च 2020 की वीडियो-बैठक रही, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आपातकालीन कोष का प्रस्ताव रखा और भारत की ओर से एक करोड़ डॉलर के प्रारंभिक योगदान की घोषणा की [19]। इसके बाद श्रीलंका ने 50 लाख डॉलर [25], अफगानिस्तान ने 10 लाख डॉलर, मालदीव ने दो लाख डॉलर और भूटान ने एक लाख डॉलर के योगदान की घोषणा की [26]। यद्यपि इसी बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने जम्मू-कश्मीर का प्रश्न उठाया [27], जो बताता है कि गैर-विवादास्पद विषयों पर भी द्विपक्षीय तनाव की छाया बनी रहती है।

इन तथ्यों से दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, सार्क का गतिरोध किसी एक घटना का परिणाम नहीं, बल्कि द्विपक्षीय तनाव के क्षेत्रीय मंच पर अतिक्रमण, सीमित आर्थिक परिणामों और असमान शक्ति-संरचना के संचित प्रभाव का परिणाम है; चार्टर में द्विपक्षीय विवादों को मंच से बाहर रखने की भावना होने के बावजूद व्यवहार में उन्हीं विवादों ने मंच की गति तय की [2], [3]। दूसरा, सार्क के औपचारिक संस्थान समाप्त नहीं हुए हैं; ठहराव मुख्यतः शिखर-स्तरीय राजनीतिक तंत्र में है।

4.2 बिस्सटेक का संस्थागत विकास

बिस्सटेक की स्थापना 1997 की बैंकॉक घोषणा से हुई; आज इसके सात सदस्य, अर्थात् बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, दक्षिण एशिया के पाँच सार्क सदस्यों तथा दो दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से मिलकर बने हैं [4], [23]। बिस्सटेक क्षेत्र में 1.8 अरब से अधिक लोग रहते हैं, जो विश्व जनसंख्या का लगभग 22 प्रतिशत है; 2022 में सदस्य देशों का संयुक्त बाह्य व्यापार 1.95 ट्रिलियन डॉलर और अनुमानित संयुक्त जीडीपी 4.5 ट्रिलियन डॉलर रहा [16]।

संस्थागत विकास की दृष्टि से 2018 के काठमांडू शिखर सम्मेलन में बिस्सटेक के लक्ष्यों को चार्टर में संहिताबद्ध करने का निर्णय लिया गया; चार्टर पर 30 मार्च 2022 को कोलंबो में हस्ताक्षर हुए और वह 20 मई 2024 से प्रभावी हुआ [16]। सचिवालय ढाका में स्थित है और सहयोग के क्षेत्र सात प्रमुख क्षेत्रों में पुनर्गठित किए गए हैं [16]।

छठा शिखर सम्मेलन 4 अप्रैल 2025 को बैंकॉक में 'समृद्ध, लचीला और उन्मुक्त बिस्सटेक' विषय के अंतर्गत संपन्न हुआ [5]। प्रधानमंत्री मोदी इसमें भाग लेने 3 अप्रैल को थाईलैंड रवाना हुए [28]। शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणामों में घोषणा-पत्र, संगठन का पहला दृष्टि-पत्र 'बैंकॉक विज़न 2030' और समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर सम्मिलित हैं [5]। समुद्री समझौते में प्रमाणपत्रों की पारस्परिक मान्यता, पोतों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार और विवाद-समाधान तंत्र का प्रावधान बताया गया है [29]। समापन पर बांग्लादेश ने अध्यक्षता ग्रहण की [5]। प्रधानमंत्री मोदी ने संगठन को सुदृढ़ करने के लिए

कई पहलें प्रस्तावित कीं [17]। इन पहलों में आपदा प्रबंधन, सतत समुद्री परिवहन, पारंपरिक चिकित्सा तथा कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के उत्कृष्टता केंद्र, मानव संसाधन विकास के लिए 'बोधि' कार्यक्रम, 2027 में प्रथम बिस्मटेक खेल और बिस्मटेक वाणिज्य मंडल की स्थापना सम्मिलित हैं [17]। इसी अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनस से भेंट की; अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद दोनों नेताओं की यह पहली प्रत्यक्ष भेंट थी [30]।

2026 में बिस्मटेक की गतिविधियाँ सुरक्षा क्षेत्र में विस्तृत होती दिखीं। जुलाई 2026 में नई दिल्ली में बिस्मटेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक हुई, जिसमें भारत ने समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तथा आतंकवाद और संगठित अपराध से निपटने में सहयोग पर बल दिया [23]। 13 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली में बिस्मटेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक हुई, जिसमें आतंकवाद-निरोध, संगठित अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी पर सहयोग का मुद्दा केंद्र में रहा [31]; यह बैठक 2018 के काठमांडू शिखर सम्मेलन में कानून-प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों के समन्वय की सहमति के लगभग आठ वर्ष बाद संभव हुई [32]। सार्क और बिस्मटेक के प्रमुख घटनाक्रम तालिका 1 में एक साथ रखे गए हैं।

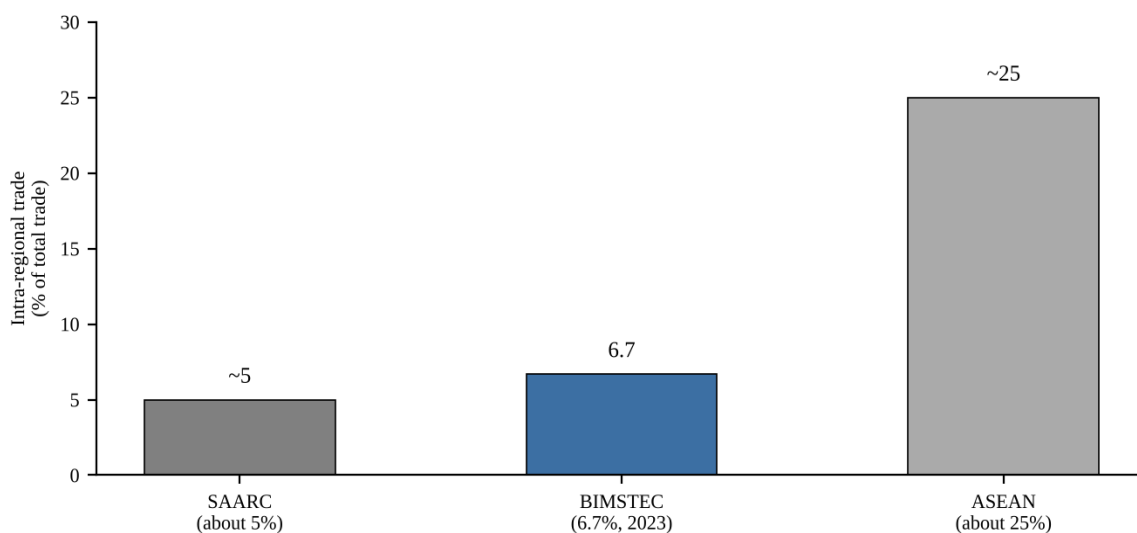
तालिका 1: सार्क और बिस्मटेक के प्रमुख घटनाक्रम, 1985-2026 (स्रोत: [2], [3], [4], [5], [16], [19], [20], [23], [24], [31], [33], [34])

वर्ष	सार्क	बिस्मटेक
1985	ढाका में प्रथम शिखर सम्मेलन; चार्टर पर हस्ताक्षर (8 दिसंबर)	कोई प्रमुख घटना नहीं
1997	कोई प्रमुख घटना नहीं	बैंकॉक घोषणा के साथ स्थापना (6 जून)
2004	इस्लामाबाद में 12वाँ शिखर सम्मेलन; साफ्टा पर हस्ताक्षर	मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए रूपरेखा समझौता; बैंकॉक में प्रथम शिखर सम्मेलन
2014	काठमांडू में 18वाँ और अंतिम शिखर सम्मेलन (नवंबर)	ढाका में सचिवालय की स्थापना
2016	उरी हमले के बाद इस्लामाबाद में प्रस्तावित 19वाँ शिखर सम्मेलन स्थगित	गोवा में ब्रिक्स-बिस्मटेक आउटरीच बैठक (अक्टूबर)
2018	कोई प्रमुख घटना नहीं	काठमांडू में चौथा शिखर सम्मेलन; चार्टर बनाने का निर्णय
2020	कोविड-19 आपातकालीन कोष पर वीडियो-बैठक (15 मार्च)	कोई प्रमुख घटना नहीं
2022	कोई प्रमुख घटना नहीं	कोलंबो में पाँचवाँ शिखर सम्मेलन; चार्टर पर हस्ताक्षर (30 मार्च)
2024	कोई प्रमुख घटना नहीं	चार्टर प्रभावी (20 मई)
2025	चार्टर दिवस की 40वीं वर्षगांठ (8 दिसंबर): पाकिस्तान के राष्ट्रपति के संदेश में गतिरोध का उल्लेख	बैंकॉक में छठा शिखर सम्मेलन (4 अप्रैल); बैंकॉक विज्ञान 2030; समुद्री परिवहन सहयोग समझौता; बांग्लादेश की अध्यक्षता

2026	बांग्लादेश द्वारा सार्क के पुनरुद्धार का आग्रह (जुलाई)	नई दिल्ली में सुरक्षा प्रमुखों की बैठक (जुलाई) और प्रथम गृह मंत्री बैठक (13 अक्टूबर)
------	--	--

4.3 सार्क और बिम्सटेक: तुलनात्मक विश्लेषण

तालिका 2 सार्क और बिम्सटेक की तुलना प्रस्तुत करती है। जनसंख्या के पैमाने पर सार्क (लगभग 1.93 अरब) बिम्सटेक (लगभग 1.8 अरब) से बड़ा है, जबकि दोनों की संयुक्त जीडीपी लगभग 4.2 से 4.5 ट्रिलियन डॉलर के बीच है [16], [18]। आँकड़ों से स्पष्ट है कि संस्थागत सक्रियता में बिम्सटेक को बढ़त है, क्योंकि उसके छह शिखर सम्मेलन हो चुके हैं, चार्टर प्रभावी है, एक दृष्टि-पत्र अपनाया गया है और मंत्री-स्तरीय बैठकों का दायरा बढ़ रहा है, जबकि सार्क 2014 के बाद शिखर स्तर पर निष्क्रिय है। परंतु आर्थिक संकेतकों में यह बढ़त मामूली है: बिम्सटेक का अंतर-क्षेत्रीय व्यापार 6.7 प्रतिशत है [14] और सार्क के लिए यह लगभग पाँच प्रतिशत है [13] (चित्र 1)। आसियान का लगभग 25 प्रतिशत का स्तर [12] दोनों संगठनों के लिए यह संकेत देता है कि संस्थागत सक्रियता और आर्थिक एकीकरण के बीच सीधा संबंध अपने-आप नहीं बनता।



चित्र 1: अंतर-क्षेत्रीय व्यापार का कुल व्यापार में अनुपात (प्रतिशत)। स्रोत: [12], [13], [14]। आँकड़े अलग-अलग वर्षों के हैं तथा सार्क और आसियान के मान अनुमानित हैं।

तालिका 2: सार्क और बिम्सटेक की तुलना (स्रोत: [2], [4], [13], [14], [16], [18], [20])

आयाम	सार्क	बिम्सटेक
स्थापना	8 दिसंबर 1985, ढाका	6 जून 1997, बैंकॉक घोषणा
सदस्य	आठ: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका	सात: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड
भौगोलिक दायरा	दक्षिण एशिया	बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती और निकटवर्ती देश; दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच सेतु
सचिवालय	काठमांडू	ढाका

अंतिम शिखर सम्मेलन	18वाँ, काठमांडू, नवंबर 2014	छठा, बैंकॉक, 4 अप्रैल 2025
चार्टर की स्थिति	1985 का चार्टर	चार्टर 30 मार्च 2022 को हस्ताक्षरित; 20 मई 2024 से प्रभावी
अंतर-क्षेत्रीय व्यापार	कुल व्यापार का लगभग 5 प्रतिशत (विश्व बैंक, 2018)	लगभग 6.7 प्रतिशत (2023)
जनसंख्या और संयुक्त जीडीपी	जनसंख्या लगभग 1.93 अरब; संयुक्त जीडीपी लगभग 4.2 ट्रिलियन डॉलर (2022)	जनसंख्या 1.8 अरब से अधिक; संयुक्त जीडीपी लगभग 4.5 ट्रिलियन डॉलर (2022)
मुक्त व्यापार ढांचा	साफ्टा: 2004 में हस्ताक्षरित, 2006 से लागू	मुक्त व्यापार के लिए 2004 का रूपरेखा समझौता; व्यापार समझौता अंतिम रूप की प्रतीक्षा में
पाकिस्तान की स्थिति	सदस्य	सदस्य नहीं

4.4 भारत की प्राथमिकताओं में परिवर्तन के कारक

अक्टूबर 2016 में गोवा में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ आयोजित ब्रिक्स-बिस्स्टेक आउटरीच बैठक इस परिवर्तन का प्रारंभिक सार्वजनिक संकेत थी; यह उरी हमले और सार्क शिखर सम्मेलन के स्थगन के कुछ ही दिनों बाद हुई [3], [34]। द्वितीयक स्रोतों के विश्लेषण से बदलाव के पाँच परस्पर जुड़े कारक चिह्नित होते हैं।

पहला कारक राजनीतिक-सुरक्षा गतिरोध है। सार्क में निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, इसलिए किसी एक सदस्य की असहमति पूरे मंच को रोक सकती है। काठमांडू (2014) और इस्लामाबाद (2016) के अनुभवों ने भारत को ऐसे मंच की ओर उन्मुख किया जिसमें पाकिस्तान सदस्य नहीं है [3], [8]। भारत पाकिस्तान पर क्षेत्रीय संपर्क परियोजनाओं को बाधित करने का आरोप लगाता रहा है [23]।

दूसरा कारक नीतिगत संरेखण है। 2014 से घोषित 'पड़ोसी प्रथम' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियाँ बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में मिलती हैं, क्योंकि यह क्षेत्र भारत के पूर्वोत्तर को बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ता है। मई 2014 के शपथ-ग्रहण समारोह में सार्क देशों के नेताओं और मई 2019 के समारोह में बिस्स्टेक देशों के नेताओं को आमंत्रित करना इसी झुकाव की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति माना जा सकता है।

तीसरा कारक संपर्क और अवसंरचना है। कालादान बहुविध परियोजना तथा भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग बिस्स्टेक भूगोल में आते हैं, और ईस्ट एशिया फोरम के अनुसार इनके पूर्ण होने में हुआ विलंब बिस्स्टेक की प्रमुख कमजोरी है [15]। इसी प्रकार 2015 का बीबीआईएन मोटर वाहन समझौता उप-क्षेत्रीय मार्ग का उदाहरण है, जिसे ऑब्ज़र्वर रिसर्च फ़ाउंडेशन ने सार्क के गतिरोध के बीच सफल उप-क्षेत्रीय पहलों में गिना [10]।

चौथा कारक आर्थिक तर्क है। सार्क में कम अंतर-क्षेत्रीय व्यापार और साफ्टा की कमजोरी के सामने बिस्स्टेक दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजारों तक पहुँच का मार्ग देता है; किंतु यह संभावना अभी साकार नहीं हुई है [14]।

पाँचवाँ कारक सामरिक-समुद्री संदर्भ है। काठमांडू पोस्ट के संपादकीय ने क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को क्षेत्रीय शक्ति-संतुलन में बदलाव के रूप में रेखांकित किया [11]। 2025 का समुद्री परिवहन सहयोग समझौता और 2026 में समुद्री सुरक्षा पर भारत का बल इसी संदर्भ में पढ़ा जा सकता है [5], [23]।

4.5 बिस्मटेक की सीमाएँ और चुनौतियाँ

आर्थिक क्षेत्र में बिस्मटेक का मुक्त व्यापार क्षेत्र का रूपरेखा समझौता 2004 में हुआ था, पर व्यापार समझौता दो दशक बाद भी अंतिम रूप की प्रतीक्षा में है; थाईलैंड की तत्कालीन प्रधानमंत्री पेतोंगतार्न शिनावाना ने बैंकॉक में इसे शीघ्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जबकि अंतर-क्षेत्रीय व्यापार 6.7 प्रतिशत पर है [14]। संपर्क परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तत्परता की कमी भी दर्ज की गई है [15]।

सदस्य देशों के आपसी संबंध भी बिस्मटेक की गति को प्रभावित करते हैं। बांग्लादेश में नेतृत्व परिवर्तन का क्रम इस प्रकार रहा: 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना की सरकार का पतन हुआ, 8 अगस्त 2024 को मुहम्मद यूनस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में शपथ ली, और 12 फरवरी 2026 के आम चुनाव के बाद 17 फरवरी 2026 को तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली [35], [36], [37]। बांग्लादेश ने अप्रैल 2025 में अध्यक्षता ग्रहण की [5]; अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत में उपस्थिति और बांग्लादेश की बीजिंग के साथ बढ़ती सक्रियता के कारण भारत-बांग्लादेश संबंधों में आए तनाव को संगठन की दिशा के लिए अनिश्चितता का कारण बताया गया है [15]। अक्टूबर 2026 में पहली बिस्मटेक गृह मंत्री बैठक में बांग्लादेश के गृह मंत्री उपस्थित नहीं हुए और वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजा गया, जबकि बांग्लादेश अध्यक्ष देश है; इसी प्रकार प्रधानमंत्री तारिक रहमान सितंबर में नई दिल्ली के ब्रिक्स आउटरीच सत्र में निमंत्रण के बावजूद सम्मिलित नहीं हुए [32]।

बिस्मटेक चार्टर का अनुच्छेद 19 सदस्य देशों से विवादों के समयबद्ध और शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास अपेक्षित करता है [14]। इस प्रावधान की वास्तविक परीक्षा सदस्य देशों के बीच उभरने वाले द्विपक्षीय तनावों में होगी।

4.6 प्रतिस्थापन या पूरकता

विवेचन में एक प्रश्न बार-बार उठता है: क्या बिस्मटेक सार्क का स्थान ले रहा है? उपलब्ध तथ्य मिश्रित चित्र देते हैं। एक ओर भारत बिस्मटेक को क्षेत्रीय सहयोग के प्रमुख मंच के रूप में बढ़ावा देता रहा है [23], जबकि दूसरी ओर पड़ोसी देशों की ओर से सार्क के पुनरुद्धार की माँग उठ रही है। फरवरी 2026 में पदभार ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री तारिक रहमान की पहली प्रेस वार्ता में सार्क के पुनरुद्धार का उल्लेख हुआ, और बांग्लादेश ने बिस्मटेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की बैठक में सार्क तथा बिस्मटेक के साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया [23], [33]; इससे पहले पूर्व अंतरिम प्रमुख मुहम्मद यूनस ने भी सार्क के पुनरुद्धार की माँग उठाई थी [23]। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भी सार्क के ठहराव पर चिंता जताई है [24]।

दूसरी ओर, बिस्मटेक पूरी तरह सार्क का स्थान नहीं ले सकता। सार्क के आठ में से तीन सदस्य, अर्थात पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव, बिस्मटेक से बाहर हैं, इसलिए इन देशों के साथ भारत के संबंध द्विपक्षीय या अन्य मंचों पर ही आगे बढ़ेंगे। साथ ही सार्क का औपचारिक ढाँचा, जिसमें चार्टर, सचिवालय और विशेष संस्थान सम्मिलित हैं, बना हुआ है और 2020 में संकट के समय उसका उपयोग भी हुआ [19]।

इसलिए 'प्रतिस्थापन' की अपेक्षा 'पुनर्क्रम' अधिक उपयुक्त शब्द प्रतीत होता है: भारत के लिए शिखर-स्तरीय क्षेत्रीय सहयोग की प्राथमिकता बिस्मटेक की ओर खिसकी है, परंतु सार्क समाप्त नहीं हुआ है; वह ठहराव की स्थिति में है।

V. CONCLUSION (निष्कर्ष)

यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि भारतीय विदेश नीति में क्षेत्रीय प्राथमिकताओं का केंद्र सार्क से बिस्मटेक की ओर खिसका है, परंतु यह परिवर्तन परित्याग नहीं, बल्कि पुनर्क्रम है। 2014 के बाद सार्क का शिखर-स्तरीय तंत्र निष्क्रिय रहा, जबकि बिस्मटेक ने चार्टर (2022 में हस्ताक्षरित, 2024 से प्रभावी), बैंकॉक विज़न 2030 और समुद्री परिवहन समझौते (2025) के रूप में संस्थागत प्रगति की।

इस परिवर्तन के प्रमुख कारक पाकिस्तान से जुड़ा राजनीतिक गतिरोध, 'पड़ोसी प्रथम' और 'एक्ट ईस्ट' नीतियों का संगम, संपर्क परियोजनाओं की आवश्यकता, आर्थिक विविधीकरण की इच्छा और बंगाल की खाड़ी में सामरिक संतुलन रहे हैं।

साथ ही बिस्मटेक की सीमाएँ स्पष्ट हैं: 6.7 प्रतिशत का अंतर-क्षेत्रीय व्यापार, लंबित मुक्त व्यापार समझौता, संपर्क परियोजनाओं में विलंब, और अध्यक्ष देश बांग्लादेश के साथ भारत के तनावपूर्ण संबंध।

नीतिगत दृष्टि से तीन बिंदु उभरते हैं। पहला, बिस्मटेक की विश्वसनीयता मुक्त व्यापार समझौते और संपर्क परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्ति पर निर्भर करेगी। दूसरा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मालदीव के साथ संबंधों के लिए बिस्मटेक से बाहर के द्विपक्षीय और अन्य मंचों की भूमिका बनी रहेगी। तीसरा, स्वास्थ्य और आपदा जैसे गैर-विवादास्पद क्षेत्रों में सार्क के ढाँचे का सीमित उपयोग एक विकल्प के रूप में खुला रह सकता है।

भविष्य के अध्ययन नीति-निर्माताओं और विशेषज्ञों के साक्षात्कार जैसे प्राथमिक आँकड़ों तथा सदस्य देशों के व्यापार-आँकड़ों के समान-वर्षीय विश्लेषण के माध्यम से इन निष्कर्षों की परीक्षा कर सकते हैं।

VI. ACKNOWLEDGMENT (आभार)

लेखक इस अध्ययन में प्रयुक्त पुस्तकों, शोध-विश्लेषणों, आधिकारिक विज्ञप्तियों और समाचार-स्रोतों के सभी लेखकों एवं संस्थानों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

REFERENCES (संदर्भ सूची)

- [1] सुमित गांगुली, *भारत की विदेश नीति: अपेक्षा और पुनरावलोकन*. नई दिल्ली, भारत: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 2018, ISBN 978-0-19-948518-5.
- [2] South Asian Association for Regional Cooperation, "SAARC Charter," *SAARC Secretariat*, Dhaka, Bangladesh, Dec. 8, 1985. [Online]. Available: <https://www.saarc-sec.org/index.php/about-saarc/saarc-charter>. Accessed: Oct. 16, 2026.
- [3] B. S. Syed, "Saarc summit put off indefinitely," *Dawn*, Oct. 1, 2016. [Online]. Available: <https://www.dawn.com/news/amp/1287281>. Accessed: Oct. 16, 2026.
- [4] BIMSTEC Secretariat, "History," *BIMSTEC*. [Online]. Available: <https://bimstec.org/history>. Accessed: Oct. 16, 2026.
- [5] BIMSTEC Secretariat, "6th BIMSTEC Summit (Apr. 4, 2025, Bangkok): Press release," Apr. 5, 2025. [Online]. Available: https://bimstec.org/images/content_page_pdf/1743843190_Press%20Release_6th%20%20Summit.pdf. Accessed: Oct. 16, 2026.
- [6] राजीव सिकरी, *भारत की विदेश नीति: चुनौती और रणनीति*. नई दिल्ली, भारत: सेज पब्लिकेशंस इंडिया, 2014.
- [7] साधना पांडेय, *भारत की विदेश नीति*. वॉलनट पब्लिकेशन, 2020, ISBN 978-93-89744-36-1.
- [8] अमन उपाध्याय, "चीन की टेंशन बढ़ाएगा BIMSTEC! पीएम मोदी की बैंकॉक यात्रा पर दुनिया की नजर, जानें क्या है पूरा प्लान," *नवभारत लाइव*, 2 अप्रैल 2025. [Online]. Available: <https://navbharatlive.com/world/bimstec-will-increase-china-tension-world-eyes-are-on-pm-modi-bangkok-visit-1174001.html/amp>. अभिगमन तिथि: 16 अक्टूबर 2026.
- [9] आज तक, "कोरोना से डरने की नहीं, साथ लड़ने की जरूरत- SAARC देशों से पीएम मोदी," *आज तक*, 15 मार्च 2020. [Online]. Available: <https://www.aajtak.in/india/video/pm-modi-addresses-saarc-video-conference-on-covid-19-coronavirus-1039179-2020-03-15>. अभिगमन तिथि: 16 अक्टूबर 2026.

- [10] Observer Research Foundation, "An impasse in SAARC," *ORF*, Jan. 4, 2017. [Online]. Available: <https://www.orfonline.org/expert-speak/an-impasse-in-saarc>. Accessed: Oct. 16, 2026.
- [11] "New regionalism" (editorial), *The Kathmandu Post*, Mar. 7, 2018. [Online]. Available: <https://kathmandupost.com/editorial/2018/03/07/new-regionalism>. Accessed: Oct. 16, 2026.
- [12] M. D. Fazil, "The irrelevance of SAARC," *South Asian Voices*, Oct. 25, 2016. [Online]. Available: <https://southasianvoices.org/the-irrelevance-of-saarc/>. Accessed: Oct. 16, 2026.
- [13] World Bank, "South Asia should remove trade barriers for mutual economic gains: New World Bank report," *World Bank*, Kolkata, India, Sep. 24, 2018. [Online]. Available: <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/09/24/south-asia-remove-trade-barriers-mutual-economic-gains-report>. Accessed: Oct. 16, 2026.
- [14] A. Ranjan, "The BIMSTEC summit in Bangkok: Potential and challenges," Institute of South Asian Studies, National University of Singapore, ISAS Brief No. 1229, Apr. 11, 2025. [Online]. Available: <https://www.isas.nus.edu.sg/papers/the-bimstec-summit-in-bangkok-potential-and-challenges>. Accessed: Oct. 16, 2026.
- [15] N. Hussain, "A reinvigorated BIMSTEC hopes to avoid regional pitfalls," *East Asia Forum*, May 14, 2025. [Online]. Available: <https://eastasiaforum.org/2025/05/13/a-reinvigorated-bimstec-hopes-to-avoid-regional-pitfalls/>. Accessed: Oct. 16, 2026.
- [16] BIMSTEC Secretariat, "BIMSTEC is poised to transform itself into a successful regional organisation," Jun. 6, 2024. [Online]. Available: https://bimstec.org/images/content_page_pdf/1717644564_Article%20on%20BIMSTEC.pdf. Accessed: Oct. 16, 2026.
- [17] Prime Minister of India, "English translation of Prime Minister of India's statement during the 6th BIMSTEC Summit," Bangkok, Thailand, Apr. 4, 2025. [Online]. Available: https://bimstec.org/images/content_page_pdf/1749179977_Statement%20by%20the%20%20Prime%20Minister%20of%20India.pdf. Accessed: Oct. 16, 2026.
- [18] World Bank, "World Development Indicators (WDI), 2022," *World Bank DataBank*. [Online]. Available: <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>. Accessed: Oct. 17, 2026.
- [19] प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार, "प्रधानमंत्री ने सार्क नेताओं से क्षेत्र में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए बातचीत की," 15 मार्च 2020. [Online]. Available: <https://www.pmindia.gov.in/?p=7247241>. अभिगमन तिथि: 16 अक्टूबर 2026.
- [20] South Asian Association for Regional Cooperation, "Agreement on South Asian Free Trade Area (SAFTA)," Islamabad, Pakistan, 2004. [Online]. Available: <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2671/download>. Accessed: Oct. 16, 2026.

- [21] S. Set, "India's regional diplomacy reaches outer space," *Carnegie Endowment for International Peace*, Jul. 3, 2017. [Online]. Available: <https://carnegieendowment.org/research/2017/07/indias-regional-diplomacy-reaches-outer-space>. Accessed: Oct. 16, 2026.
- [22] "Efforts are on to stir SAARC, says Gyawali," *The Kathmandu Post*, Sep. 30, 2018. [Online]. Available: <https://kathmandupost.com/miscellaneous/2018/09/30/efforts-are-on-to-stir-saarc-says-gyawali>. Accessed: Oct. 16, 2026.
- [23] A. Bhaumik, "Bangladesh seeks revival of SAARC; India pushes maritime security cooperation within BIMSTEC framework," *Deccan Herald*, Jul. 16, 2026. [Online]. Available: <https://www.deccanherald.com/amp/story/india/bangladesh-seeks-revival-of-saarc-india-pushes-maritime-security-cooperation-within-bimstec-framework-4076389>. Accessed: Oct. 16, 2026.
- [24] K. Muraad, "Pakistan ready to work for regional trade, linkages: President," *Associated Press of Pakistan*, Islamabad, Pakistan, Dec. 7, 2025. [Online]. Available: <https://www.app.com.pk/?p=1125258>. Accessed: Oct. 16, 2026.
- [25] प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत सरकार, "प्रधानमंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति को धन्यवाद दिया," 23 मार्च 2020. [Online]. Available: <https://www.pmindia.gov.in/?p=7287441>. अभिगमन तिथि: 16 अक्टूबर 2026.
- [26] "Several SAARC nations announce contributions to COVID-19 emergency fund," *The Morning*, Mar. 21, 2020. [Online]. Available: <https://www.themorning.lk/several-saarc-nations-announce-contributions-to-covid-19-emergency-fund>. Accessed: Oct. 16, 2026.
- [27] PTI, "Modi proposes SAARC fund to tackle coronavirus, lays stress on joint efforts," *The Week*, Mar. 15, 2020. [Online]. Available: <https://www.theweek.in/news/india/2020/03/15/modi-proposes-saarc-fund-to-tackle-coronavirus-lays-stress-on-joint-efforts.amp.html>. Accessed: Oct. 16, 2026.
- [28] आज तक, "बैकॉक पहुंचे PM मोदी, BIMSTEC के मंच पर दिखेगा 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' का दम," *आज तक*, 3 अप्रैल 2025. [Online]. Available: <https://www.aajtak.in/india/news/story/pm-narendra-modi-emplanes-for-bangkok-thailand-to-participate-6th-bimstec-summit-ntc-rpti-2206997-2025-04-03>. अभिगमन तिथि: 16 अक्टूबर 2026.
- [29] B360 Nepal, "6th BIMSTEC summit concludes with Bangkok Vision 2030, maritime agreement approval," *B360 Nepal*, Apr. 4, 2025. [Online]. Available: <https://www.b360nepal.com/detail/24874/6th-bimstec-summit-concludes-with-bangkok-vision-2030-maritime-agreement-approval>. Accessed: Oct. 16, 2026.
- [30] ANI, "PM Modi meets Bangladesh Chief Adviser Muhammad Yunus on sidelines of BIMSTEC Summit," *The Tribune*, Apr. 4, 2025. [Online]. Available: <https://www.tribuneindia.com/news/world/pm-modi-meets-bangladesh-chief-adviser-muhammad-yunus-on-sidelines-of-bimstec-summit>. Accessed: Oct. 16, 2026.
- [31] ANI, "India committed to BIMSTEC Convention to tackle terrorism, organised crime, drug trafficking: Amit Shah at 1st BIMSTEC HMM," *Devdiscourse*, Oct. 13, 2026. [Online]. Available: <https://www.devdiscourse.com/article/international/3991378-india-committed-to-bimstec>

convention-to-tackle-terrorism-organised-crime-drug-trafficking-amit-shah-at-1st-bimstec-hmm.
Accessed: Oct. 17, 2026.

[32] U. Jalali, "Bangladesh Home Minister to skip first BIMSTEC meet in Delhi," *The Tribune*, Oct. 13, 2026. [Online]. Available: <https://www.tribuneindia.com/news/india/bangladesh-home-minister-to-skip-first-bimstec-meet-in-delhi/amp>. Accessed: Oct. 16, 2026.

[33] K. Padmanabhan, "Bangladesh pitches SAARC revival at BIMSTEC meet, calls for closer regional cooperation," *ThePrint*, Jul. 16, 2026. [Online]. Available: <https://theprint.in/diplomacy/bangladesh-pitches-saarc-revival-at-bimstec-meet-calls-for-closer-regional-cooperation/2988153/>. Accessed: Oct. 16, 2026.

[34] BIMSTEC, "BIMSTEC Leaders' Retreat 2016 outcome document: Goa, India," Goa, India, Oct. 16, 2016. [Online]. Available: <https://old.mofa.gov.np/?p=2955>. Accessed: Oct. 16, 2026.

[35] M. Sharma, "Nobel laureate Muhammad Yunus takes oath as head of Bangladesh's interim government," *WION*, Aug. 8, 2024. [Online]. Available: <https://www.wionews.com/south-asia/nobel-laureate-muhammad-yunus-takes-over-as-chief-adviser-of-bangladeshs-interim-government-748510/amp>. Accessed: Oct. 16, 2026.

[36] Al Jazeera Staff and News Agencies, "Bangladesh's interim leader Yunus steps down as new gov't set to take over," *Al Jazeera*, Feb. 16, 2026. [Online]. Available: <https://www.aljazeera.com/news/2026/2/16/bangladeshs-interim-leader-yunus-steps-down-as-new-govt-set-to-take-over>. Accessed: Oct. 16, 2026.

[37] News On AIR, "BNP chief Tarique Rahman sworn in as Prime Minister of Bangladesh," *All India Radio*, Feb. 17, 2026. [Online]. Available: <https://www.newsonair.gov.in/bangladesh-bnp-chief-tarique-rahman-sworn-in-as-prime-minister>. Accessed: Oct. 16, 2026.

Copyright & License:

© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.